RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2022-2024 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com

DPR No. N-193
www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 05 JULY TO 11 JULY 2023 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 08 ■ अंक 42 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

जीएसटी से लगातार भर रहा खजाना Page 3

एयरपोर्ट पर रोके जाएंगे बिना पंजीकरण वाले प्लास्टिक उत्पाद Page 4

दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा विकसित एनर्जी ड्रिंक तैयार Page 5

editoria!

सहकारिता से समाधान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के गांवों और किसानों के विकास के लिए सहकारिता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के गांवों और किसानों के विकास के लिए सहकारिता सम्मेलन में सहकारिता को देश के सामाजिक और आर्थिक बदलाव के लिए अहम बताया गया. कृषि प्रधान देश होने के नाते भारत में सहकारिता क्षेत्र के महत्व को गुलामी के दौर में ही समझ लिया गया था. 18वीं सदी में शुरू हुई औद्योगिक क्रांति ने भारत में ग्रामोद्योगों की कमर तोड़ दी, और ग्रामवासियों के लिए कृषि आजीविका का सबसे बड़ा साधन बन गयी, लेकिन विभिन्न कारणों से कृषि का काम गैर-लाभकारी होता गया और किसान साहूकारों के चंगुल में फंसते गये. ऐसे में किसानों के लिए सस्ता कर्ज उपलब्ध कराने की एक वैकल्पिक व्यवस्था की जरूरत महसूस की जाने लगी और सहकारी संस्थाओं का उदय होता गया. आजादी के बाद जब देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, तो उसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के साथ-साथ सहकारी क्षेत्र को भी शामिल किया गया. भारतीय सहकारी विकास निगम, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नैफेड), भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड (इफ्को) तथा अमूल जैसी सहकारी संस्थाओं की बदौलत भारत में गांवों और किसानों का जीवन बेहतर हुआ है, अभी देश में लगभग 10 लाख सहकारी समितियां हैं, जिनमें से एक लाख से ज्यादा वित्तीय सहकारी समितियां हैं, लेकिन कुप्रबंधन, गैर-जवाबदेही और भ्रष्टाचार जैसे कारणों से कई सहकारी या कोऑपरेटिव बैंक बंद हो गये. सहकारिता सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी कहा कि एक समय था, जब सहकारी समितियां भ्रष्टाचार, कुव्यवस्था और राजनीति में लिप्त रहती थीं, लेकिन अब सुधारों से यह क्षेत्र समृद्धि की ओर अग्रसर है. इन प्रयासों में वर्ष 2021 में सहकारिता क्षेत्र की देख-रेख के लिए एक नये सहकारिता मंत्रालय का गठन करने जैसे फैसले शामिल हैं. भारत में कृषि की स्थिति को लेकर चिंता जतायी जाती रही है. अक्सर ऐसा सुनने में आता है कि खेती अब फायदे का काम नहीं रहा और किसान खेती छोड़ रहे हैं. किसानों के आत्महत्या करने की खबरों से भी ऐसी चिंताओं को बल मिलता है. किसान की खेती और कमाई की एक सुचारु व्यवस्था जारी रहे और वह कर्ज के चंगुल में न फंसे, इसके लिए सहकारिता की व्यवस्था कारगर साबित हो सकती है. सहकारिता क्षेत्र की मजबूती से किसानों की आर्थिक सुरक्षा और देश की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी.

डॉलर की जगह भारत ने अपनाया युआन

रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए जरूरत

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों के चलते हो रहे बदलावों के बीच भारत ने डॉलर की जगह युआन का इस्तेमाल करना शुरू किया है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट बताती है कि भारतीय रिफाइनर रूस से आ रहे कच्चे तेल का कुछ पेमेंट अब डॉलर की जगह चीन की करेंसी युआन में कर रहे हैं।

खबर में मामले से अवगत सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि रूस पर लगे पश्चिमी प्रतिबंधों के चलते भारतीय रिफाइनर को ऐसा करना पड़ रहा है। रूस ने पिछले साल फरवरी में यूक्रेन पर हमला कर दिया था। उसके बाद से अभी तक पूर्वी यूरोप में युद्ध जारी है। इसके चलते अमेरिका की अगुवाई में पश्चिमी देशों ने रूस के ऊपर कई कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। इन प्रतिबंधों के कारण भारतीय रिफाइनर रूसी कच्चे तेल का पेमेंट डॉलर में नहीं कर पा रहे हैं।

वैश्विक व्यापार में ये बदलाव

रूस पर लगे प्रतिबंधों का ही असर है कि वैश्विक व्यापार में भी बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। रूस अभी भारत के लिए कच्चे तेल का सबसे बड़ा सप्लायर बन चुका है और भारत उसका सबसे बड़ा खरीदार बन गया है। इसके साथ-साथ रूस अब चीन का भी सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है, वहीं भारत के बाद चीन रूस के कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है।

युआन को प्रमोट कर रहा चीन

भारतीय रिफाइनर रूसी कच्चे तेल का कुछ पेमेंट युआन में ऐसे समय कर रहे हैं, जब चीन अपनी करेंसी को नई ग्लोबल करेंसी के रूप में प्रचारित कर रहा है। डॉलर लंबे समय से ग्लोबल करेंसी की भूमिका में है। हालांकि मौजूदा हालात में डॉलर का दबदबा कम होता नजर आ रहा है। रूस के ऊपर प्रतिबंधों से भी डॉलर का दबदबा कम हुआ है, जबकि युआन का महत्व बढ़ गया है।

इन कंपनियों ने किया पेमेंट

भारत सरकार के एक सूत्र ने रॉयटर्स को बताया है कि अगर बैंक डॉलर में ट्रेड सेटल नहीं कर रहे हैं तो कुछ रिफाइनर उन्हें युआन जैसी दूसरी करेंसी में पेमेंट कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि सबसे पहले यह काम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने जून में किया था। उन्होंने यह भी दावा किया कि भारत की कम से कम 2 प्राइवेट रिफाइनर कंपनियां भी युआन में पेमेंट कर रही हैं। भारत में अभी तीन रिफाइनर कंपनियां हैं, जिनके नाम हैं- रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नायरा एनर्जी और एचपीसीएल मित्तल एनर्जी लिमिटेड।

कच्चा तेल 76 डॉलर प्रति बैरल के करीब, पेट्रोल-डीजल की कीमत स्थिर

नई दिल्ली। एजेंसी

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में मामूली बढ़त हुई है। ब्रेंट क्रूड का भाव 76 डॉलर प्रति बैरल और डब्ल्यूटीआई क्रूड भी 71 डॉलर प्रति बैरल के करीब है। हालांकि, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं गैस विपणन कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है।

इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक बुधवार को दिल्ली में पेट्रोल 96.72 रुपये, डीजल 89.62 रुपये, मुंबई में पेट्रोल 106.31 रुपये, डीजल 94.27 रुपये, कोलकाता में पेट्रोल 106.03 रुपये, डीजल 92.76 रुपये, चेन्नई में पेट्रोल 102.63 रुपये और डीजल 94.24 रुपये प्रति लीटर दर पर उपलब्ध है। भारत में, लोग बढ़ती उम्र में दृष्टि को याददाश्त और मोबिलिटी से भी अधिक अहमियत देते हैं ज्यादातर भारतीय स्पष्ट दृष्टि के लिए कैटरेक्ट सर्जरी पर निवेश के इच्छुक हैं। इस सर्वे से एक और दिलचस्प पहलू यह भी सामने आया कि करीब 54प्रतिशत भारतीय चश्मा लगाने की वजह से खुद को बूढ़ा समझते हैं जबकि 50 वर्ष से अधिक उम्र के 92प्रतिशत भारतीय चश्मे से पीछा छुड़वाने के लिए लैंस पर खर्च करने के लिए तैयार हैं। जहां तक कैटरेक्ट सर्जरी के बारे में जानकारी का सवाल है 59 प्रतिशत लोगों का मानना है कि वे किसी आइ केयर प्रोफेशनल से परामर्श लेंगे जबकि 39 प्रतिशत और 37 प्रतिशत ने क्रमश परिवार और दोस्तों से यह सलाह लेने की तथा 36 प्रतिशत ने स्वास्थ्य संबंधी वेबसाइटों से जानकारी हासिल करने की बात स्वीकार की। सर्वे के मुताबिक, दुनियाभर में जिन भी लोगों ने एडवांस कैटरेक्ट सॉल्यूशंस का इस्तेमाल किया है वे यह मानते हैं कि इससे उनकी विजन में ही नहीं बल्कि जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है।

महत्त्वपूर्ण खनिजों की सूची जारी, पहली लिस्ट में की गई 30 मिनरल्स की पहचान

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

भारत ने अपनी रणनीतिक संसाधन सुरक्षा बढ़ाने के एक महत्वपूर्ण कदम के तहत पहली आधिकारिक महत्वपूर्ण खनिजों की सूची जारी की है। इस सूची में देश की आर्थिक वृद्धि और तकनीकी विकास के लिए महत्वपूर्ण 30 खनिजों की पहचान की गई है। इस अग्रणी कदम का मकसद आयात की निर्भरता कम करना, आपूर्ति श्रृंखला में लचीलेपन का दायरा बढ़ाना और देश के शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य का समर्थन करना है। केंद्रीय कोल, खनन और संसदीय मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बुधवार को नई दिल्ली में 'भारत के महत्वपूर्ण खनिज' से जुड़ी रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि भारत 'आत्मनिर्भर भारत' बनने के लिए तैयार हो रहा है। खनन मंत्रालय द्वारा तैयार महत्वपूर्ण खनिजों की सूची में विभिन्न उद्योगों जैसे रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, अक्षय ऊर्जा, दूरसंचार और परिवहन के लिए आवश्यक खनिजों की एक विविध श्रृंखला शामिल है। इस सूची में 30 खनिज शामिल हैं, जिनमें 17 दुर्लभ पृथ्वी तत्व (आरईई) और छह प्लैटिनम-समूह के तत्व (पीजीई) शामिल हैं जिनमें से प्रत्येक को उनके आर्थिक महत्व और भारत के भूवैज्ञानिक भंडार में सीमित उपलब्धता के आधार पर महत्वपूर्ण तत्व के रूप में नामित किया गया है।

चीन ने सेमीकंडक्टर चिप्स में इस्तेमाल होने वाले मेटल्स के एक्सपोर्ट पर लगाया प्रतिबंध

भारत पर कितना पड़ेगा असर

नई दिल्ली। एजेंसी

चीन ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए इन दो धातुओं के निर्यात को प्रतिबंधित करने का फैसला किया है। अब इन दोनों धातुओं को चीन से बाहर भेजने के लिए निर्यातकों को लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा और विदेशी खरीदारों और उनके साथ हुए सौदे का पूरा विवरण चीन की सरकार को देना होगा। सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाली इन धातुओं के निर्यात पर लगाया गया ये प्रतिबंध चीन, अमेरिका और यूरोप के बीच छिडे़ टेक्नोलॉजी वार का नतीजा है

चीन ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए सेमीकंडक्टर चिप्स को बनाने में इस्तेमाल होने वाली दो महत्वपूर्ण धातुओं गैलियम और जर्मेनियम के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। चीनी सरकार ने 3 जुलाई को ऐलान किया कि 1 अगस्त से इन दोनों धातुओं के निर्यात पर अंकुश लगाया जाएगा। इसके साथ ही इनके केमिकल कम्पाउंड्स के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। ये खबर ऐसे समय में आई हैं जब भारत सहित तमाम देश सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए आक्रामक रूप से अपनी सेमीकंडक्टर उत्पादन क्षमता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।

दूरसंचार, सेमीकंडक्टर और रक्षा उद्योग पर पड़ेगा असर

यूरोप एक औद्योगिक संगठन क्रिटिकल रॉ मटेरियल एलायंस (सीआरएमए) का कहना है कि चीन ये ऐलना काफी अहम है क्योंकि चीन ग्लोबल जर्मेनियम उत्पादन में लगभग 60 फीसदी और गैलियम उत्पादन में लगभग 80 फीसदी हिस्सेदारी रखता है। इस प्रतिबंध से भारत के दूरसंचार, सेमीकंडक्टर और रक्षा उद्योग पर असर पड़ सकता है। बीजिंग ने कहा है कि चीन ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन दो धातुओं के निर्यात को प्रतिबंधित करने का फैसला किया है। अब इन दोनों धातुओं को चीन से बाहर भेजने के लिए निर्यातकों को लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा और विदेशी खरीदारों और उनके साथ हुए सौदे का पूरा विवरण चीन की सरकार को देना होगा।

सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाली इन धातुओं के निर्यात पर लगाया गया ये प्रतिबंध चीन, अमेरिका और यूरोप के बीच छिड़े टेक्नोलॉजी वार का नतीजा है। बता दें कि अमेरिका ने अक्टूबर 2022 में चीन के होने वाले सेमीकंडक्टर और उपकरणों के निर्यात में कटौती करने के लिए नए नियम लागू किए थे। इसका बदला लेने के लिए चीन ने गैलियम और जर्मेनियम के निर्यात पर प्रतिबंध का ऐलान किया है।

बताते चलें कि गैलियम और जर्मेनियम प्राकृतिक रूप से नहीं मिलते। आमतौर पर ये धातुएं एल्यूमीनियम और जिंक जैसी धातुओं को बनाते वक्त बॉय प्रोडक्ट के तौर पर मिलती हैं। ये दोनों धातुएं बहुत ज्यादा अहम इसलिए हैं क्योंकि इनका इस्तेमाल सेमीकंडक्टर, कम्यूनिकेशन और डिफेंस उपकरणों में लगने वाले चिप्स को बनाने में किया जाता है।

भारत पर क्या होगा असर

आयात पर निर्भरता को देखते हुए इन दोनों धातुओं के निर्यात पर चीन के प्रतिबंधों से भारत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होगा। गैलियम का इस्तेमाल सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड, एलईडी डिवाइसेज, विशेष तरह के थर्मामीटर और बैरोमीटर सेंसर को बनाने में किया जाता है। जबकि जर्मेनियम का इस्तेमाल ऑप्टिकल फाइबर, सौर सेल, कैमरा और माइक्रोस्कोप लेंस, इन्फ्रारेड नाइट विजन सिस्टम और पोलीमराइजेशन कैटलिस्ट को बनाने में किया जाता है। चीन के प्रतिबंधों से इन प्रोडक्ट्स को देश में ही बनाने की भारत की योजना प्रभावित होगी। इसके अलावा निकट की अवधि में चीन के इस प्रतिबंध से चिप्स पर आधारित उपकरणों के आयात पर भी प्रभाव पड़ सकता है।

क्या है भारत सरकार का रुख

भारत सरकार ने 28 जून को गैलियम और जर्मेनियम सहित 30 महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान करते हुए कहा था कि लिस्टेड खनिज देश के आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं। सरकार ने कहा कि इन महत्वपूर्ण खनिजों की सूची उन खनिजों की पहचान करने और प्राथमिकता देने के लिए डिज़ाइन की गई है जो विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के लिए जरूरी हैं।

देश में गैलियम या जर्मेनियम का प्राथमिक स्रोत नहीं

भारत इन दोनों धातुओं के लिए मुख्य रूप से आयात पर निर्भर है। देश में गैलियम या जर्मेनियम का प्राथमिक स्रोत नहीं है। एल्युमिना का उत्पादन करते समय गैलियम को बॉय प्रोडक्ट के तौर पर हासिल किया जाता है। भारत में दो प्लांट्स में पहले गैलियम बना था। उत्तर प्रदेश के रेनुकूट में स्थित हिंडाल्को के प्लांट और ओडिशा के दमनजोडी में स्थित नाल्को के एल्यूमिना रिफाइनरी में अतीत में गैलियम मिला था। जर्मेनियम भी देश में उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में इसकी जरूत आयात के जरिए पूरी की जाती है। पिछले महीने खनन मंत्रालय की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि 33 में से 17 एलीमेंट ऐसे हैं जिनके साथ आपूर्ति का जोखिम जुड़ा हुआ है। ये एलीमेंट देश के लिए आर्थिक तौर पर काफी अहम हैं। इस रिपोर्ट में गैलियम का नाम भी शामिल था। जर्मेनियम सहित कुल 7 एलीमेंट्स की पहचान हाई सप्लाई रिस्क वाले एलीमेंट्स के रूप में की गई है।

अमेरिका ने भारत को दिया झटका

MEPC में जैव ईंधन पर भारतीय मसौदा प्रस्ताव को रोका

लंदन। एजेंसी

अमेरिका ने सोमवार को एमईपीसी सत्र में भारत द्वारा रखे गए जैव ईंधन पर एक मसौदा प्रस्ताव को अपनाने से रोक दिया। उसने इस मामले पर और चर्चा की मांग की। बता दें कि भारत का मसौदा एमईपीसी संकल्प में जैव ईंधन को आगे बढ़ाना है। इस मसौदा प्रस्ताव का उद्देश्य जैव ईंधन के उपयोग को सुविधाजनक बनाना और जीएचजी उत्सर्जन में कमी लाना है। अमेरिका ने सोमवार को एमईपीसी सत्र में भारत द्वारा रखे गए जैव ईंधन पर एक मसौदा प्रस्ताव को अपनाने से रोक दिया। इसे अंतिम रूप देने के लिए वायु प्रदूषण और ऊर्जा दक्षता पर एक कार्य समूह को सिफारिश करने से पहले इस मामले पर और चर्चा की मांग की।

अमेरिका ने क्यों उठाया यह कदम?

सूत्रों ने बताया कि अमेरिका सोमवार सुबह समुद्री पर्यावरण संरक्षण समिति (MEPC) के 80वें सत्र में विचार-विमर्श में इसे उठाए बिना यह सुझाव दिया। सूत्रों का कहना है कि अमेरिका द्वारा उठाया गया विरोध इस तथ्य के कारण हो सकता है कि ईंधन में गिरावट के रूप में जैव-ईंधन को बढ़ावा देने से अमोनिया और हाइड्रोजन जैसे अन्य हरित ईंधन के प्रचार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जिस ईंधन पर अमेरिका पैसा लगा रहा है।

क्या है भारत का मसौदा?

भारत का मसौदा एमईपीसी संकल्प में जैव ईंधन को आगे बढ़ाना है। इस मसौदा प्रस्ताव का उद्देश्य जैव ईंधन के उपयोग को सुविधाजनक बनाना और जीएचजी उत्सर्जन में कमी लाना है। एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल के प्रतिनिधि ने कहा कि इंटरसेशनल वर्किंग ग्रुप ने इस पर चर्चा की और समूह ने बहुमत से माना कि इसकी तत्काल आवश्यकता है। वायु प्रदूषण और ऊर्जा दक्षता पर वर्किंग ग्रुप द्वारा इस पर आगे विचार किया जाना चाहिए।

प्लास्टिक के तिरपाल का होता रहेगा इस्तेमाल

सीपीसीबी ने प्रतिबंध हटाया

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी माना कि तिरपाल एसयूपी का हिस्सा नहीं है। इतना ही नहीं इसकी जरूरत का दायरा देखते हुए भी इस पर लगी रोक हटाने का निर्णय लिया गया। सोमवार को सीपीसीबी की निदेशक दिव्या सिन्हा की ओर से इस बाबत लिखित आदेश भी जारी कर दिया गया। प्लास्टिक के तिरपाल का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है। रोज लगभग 1000 टन तिरपाल का उत्पादन होता है। तिरपाल अब सिंगल यूज प्लास्टिक (एसयूपी) का हिस्सा नहीं होगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने पूर्व निर्णय में परिवर्तन करते हुए इसे एसयूपी की पैकेजिंग श्रेणी से बाहर कर दिया है। सीपीसीबी की ओर से इस आशय का लिखित आदेश भी जारी कर दिया गया है।

मतलब, अब तिरपाल का फिर से कृषि कार्यों, आपदा प्रबंधन और तमाम अन्य जरूरतों के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। बता दें कि प्लास्टिक के तिरपाल का इस्तेमाल देश में बड़े पैमाने पर किया जाता है। रोज लगभग 1000 टन तिरपाल का उत्पादन होता है। मानसून के दिनों में तो इसकी खपत भी इतनी ही रहती है। अगर कहीं बाढ़ आ जाए, तो अस्थायी बांध बनाने, तेज वर्षा के दौरान जान-माल की रक्षा के लिए, गोदामों में और ट्रकों से लाने ले जाने में सामान को सुरक्षित रखने के लिए, निर्माण कार्यों में, कृषि कार्यों मसलन-फसल को पानी से बचाने, खेतों में पानी रोकने, मिट्टी की नमी बनाए रखने, ग्रीन हाउस में और गरीब लोगों के लिए अस्थायी शेल्टर बनाने सहित और भी ढेरों कार्यों में प्लास्टिक तिरपाल का इस्तेमाल होता है। इसके बावजूद सीपीसीबी ने इसे एसयूपी में ही शामिल कर लिया था। इससे इस उद्योग से जुड़े लोग ही नहीं, तिरपाल के उपयोगकर्ता भी बहुत परेशान थे।

तिरपाल मैन्युफैक्चरर्स मेंबर्स एसोसिएशन ने सीपीसीबी में यह प्रतिबंध हटाने का लिखित अनुरोध दिया और यह भी स्पष्ट करने की कोशिश की कि यह एसयूपी नहीं है। तिरपाल अमूमन 50 से 300 माइक्रोन तक की मोटाई वाले होते हैं और बार-बार इस्तेमाल होते हैं। इसीलिए पर लगी रोक वापस ले ली जाए। इस पर पिछले सप्ताह सीपीसीबी की 200वीं बोर्ड बैठक में भी यह मुद्दा उठा और सदस्यों ने तिरपाल को एसयूपी से बाहर करने का समर्थन किया। सीपीसीबी ने भी माना कि तिरपाल एसयूपी का हिस्सा नहीं है। इतना ही नहीं, इसकी जरूरत का दायरा देखते हुए भी इस पर लगी रोक हटाने का निर्णय लिया गया। सोमवार को सीपीसीबी की निदेशक दिव्या सिन्हा की ओर से इस बाबत लिखित आदेश भी जारी कर दिया गया। इस आदेश के बाद तिरपाल निर्माताओं और विक्रेताओं ने तो राहत की सांस ली ही है, इसका उपयोग करने वालों को भी सुविधा मिलने की संभावना है।

इनका कहना है

सीपीसीबी ने तकनीकी गलती से तिरपाल को प्लास्टिक पैकेजिंग की सूची में डाल दिया था। इससे हमारे उद्योग पर बहुत प्रभाव पड़ा। महीनों तक संघर्ष किया और सीपीसीबी ने गुहार लगाई। अब जाकर हमें एसयूपी की सूची से बाहर किया गया है। उम्मीद है कि इससे उद्योग वापस पटरी पर आ पाएगा।

-राधेश्याम गुप्ता, अध्यक्ष, दिल्ली प्लास्टिक एग्रीकल्चर पाइप एंड तिरपाल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन

तिरपाल निर्माता लंबे समय से गुहार लगा रहे थे कि उन्हें एसयूपी से बाहर किया जाए। सीपीसीबी ने तमाम पहलुओं को जांचने-परखने और प्लास्टिक तिरपाल की बड़े पैमाने पर जरूरत को देखते हुए इस पर एसयूपी के तहत लगी रोक हटा ली है। सीपीसीबी के इस निर्णय से बड़ी राहत मिलेगी।

-डा. अनिल गुप्ता, सदस्य, सीपीसीबी

जीएसटी से लगातार भर रहा खजाना

गुड्स एंड सर्विस टैक्स ने बदला इकोनॉमी का आकार

नई दिल्ली। एजेंसी

जीएसटी यानी माल एवं सेवा कर (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) को लागू हुए छह साल पूरे हो गए हैं। वित्त मंत्रालय ने 1 जुलाई को जून 2023 महीने के जीएसटी आंकड़ों की घोषणा की। जीएसटी से सरकार को जून महीने में 1.61 लाख करोड़ रुपये मिले। यह साल भर पहले की तुलना में 12 फीसदी अधिक है। मई महीने में भी जीएसटी कलेक्शन में 12 फीसदी की बढ़ोतरी देखने को मिली थी। सरकार ने छह साल पहले जीएसटी की व्यवस्था लागू की थी। हालांकि, इसकी आलोचना अब भी होती है, लेकिन इन वर्षों में जीएसटी न केवल सरकारी खजाने को भर रही है, बल्कि स्थिर भी हो गयी है।

अप्रैल महीने में जीएसटी ने अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन दिखलाया था और सरकार को इससे 1.87 लाख करोड़ रुपयों की प्राप्ति हुई थी, मई में यह आंकड़ा घटकर 1.57 लाख करोड़ रुपए हुआ और इस महीने यह बढ़कर 1.61 लाख करोड़ रुपए हो गया है। जीएसटी के 6 वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो ऐसे मौके अब तक 6 बार आए हैं, जब जीएसटी का आंकड़ा 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है। चार महीने ऐसे रहे हैं, जब जीएसटी का कलेक्शन 1.60 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है। वैसे, जून ऐसा लगातार पंद्रहवां महीना है, जब जीएसटी ने 1.40 लाख करोड़ का आंकड़ा पार किया है।

जीएसटी क्यों है अलग और क्या हैं लाभ

इसके बारे में बात करने से पहले टैक्स की फिलॉसफी यानी दर्शन समझना चाहिए। टैक्स तो किसी भी वेलफेयर स्टेट में बेहद जरूरी है, क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं जो निजी तौर पर मुहैया नहीं करायी जा सकती, तो हरेक नागरिक टैक्स देता है और उसके बदले सरकार सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर और पूरा सिस्टम यानी जुडिशियरी, लेजिस्लेचर वगैरह काम करता है। यानी, हमारा पूरा सिस्टम जैसे चलता है। टैक्स का कलेक्शन सामान्य तौर पर तो नागरिकों की आय पर होता है, जो डायरेक्ट टैक्स है और यह इंडिविजुअल होता है। उसी तरह पूरी इकोनॉमी में किसी का इनकम आता है, तो किसी का खर्च भी होता है। यह गुड्स और इनकम टैक्स के दायरे में आया।

यह पहले कई स्वरूपों में लागू होता था, इसमें बहुत अधिक विरोधाभास था और कई तरह के टैक्स थे। इन सब को सरकार ने एक कर दिया और कहा कि केंद्र और राज्य इसे आपस में बांट लेंगे। इसी बात को साफ करते हुए डीएमआई पटना में प्रोफेसर सूर्यभूषण कहते हैं, 'पहले डिस्टॉर्शन टैक्स में काफी था। लोगों को रीयल प्राइस नहीं पता चलता था। कंज्यूमर अंधेरे में रहता था। पहले स्थानीय स्तर पर सरकारें अलग टैक्स भी लगा देती थीं, जिससे दाम भी बढ़ जाते थे। अब भी यह कुछ चीजों पर है। जीएसटी की तरफ जाने का मुख्य कारण था कि अधिकांश विकसित देश इसी का इस्तेमाल करते हैं और चूंकि हम यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं, तो इसलिए फिफ्टी-फिफ्टी का शेयर राज्य और केंद्र की सरकार बांट लेती है।

जीएसटी ने दिए फायदे ही फायदे

जीएसटी के फायदे जानने हों तो एक छोटा सा उदाहरण लेना काफी होगा। जैसे, साबुन खरीदने हम जाते हैं, तो उसका एक अधिकतम खुदरा मूल्य यानी एमआरपी होता है। इसमें हमें यह नहीं पता होता था कि हम टैक्स कितना दे रहे हैं, वह इनक्लूडेड होता था और फिर स्टेट का सेल्स टैक्स होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रोडक्शन पर टैक्स था, वह भी लगता था। यह भी हो सकता था कि उतना टैक्स नहीं भी लगता था, कुछ कम भी होता था, लेकिन स्पष्टता नहीं था। अभी अगर हम 10 रुपए का साबुन खरीदते हैं, तो स्पष्टता होती है कि उसमें कितना रुपया टैक्स का है और उसमें भी सेंटर का कितना है और स्टेट का कितना है? जीएसटी के विरोध की एक वजह यह थी कि स्पष्टता कानून में नहीं थी, टैक्स-स्लैब बहुत उल्टा सीधा था। अनिवार्य वस्तुओं पर जीएसटी अधिक था, जबकि विलासिता के वस्तुओं पर बहुत कम टैक्स था, यही वजह थी कि जीएसटी का जब लॉ बना तो सरकार ने इसके ड्राफ्ट में सैकड़ों संशोधन किए। उसके बाद भी सीख-सीख कर कई सारे बदलावों के बाद मौजूदा दौर में जीएसटी है, जो हमारे आर्थिक तंत्र का आज मजबूत हिस्सा है।

सार्वभौमिक है जीएसटी

अभी हाल ही में राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने एक अखबार में अपने आलेख में जीएसटी को सरकारी तंत्र में अप्रत्यक्ष कर-संग्रह का ऐतिहासिक रूपांतरण बताया है। उन्होंने कहा है कि इसके तीनों साझीदारों यानी सरकार, उद्योग और करदाता की ही जिंदगी में जीएसटी से महत्वपूर्ण बदलाव आया है और अब लोग इस बात को स्वीकार भी रहे हैं। वह बताते हैं कि उपभोक्ता आखिरी पैमाना है किसी भी कार्यक्रम की सफलता का और इस पैमाने पर जीएसटी पूरी तरह सफल है। यह सार्वभौमिक है और सभी स्टेकहोल्डर्स के लिए है। जीएसटी के पारदर्शी और एक जैसे टैक्स ढांचे की वजह से उपभोक्ता अब पूरी तरह सूचित हो गया है। पहले वह कई तरह के करों के जाल में फंसता था, अब ऐसा नहीं है।

कर व्यवस्था को बनाए रखना जरूरी

एक सर्वे के मुताबिक ये तीनों ही स्टेकहोल्डर्स जीएसटी से बहुमत में खुश हैं और यह जीएसटी कलेक्शन के आंकड़ों से साफ है। इस बार भी जून महीने के आंकड़े को देखें तो उसमें सेंट्रल जीएसटी (ण्डएऊ) से 31,013 करोड़ रुपये, स्टेट जीएसटी (एउएऊ) से 38,292 करोड़ रुपये और इंटीग्रेटेड जीएसटी (घ्डएऊ) से 80,292 करोड़ रुपये हासिल हुए हैं। इसमें आयात पर वसूले गए 39,095 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। सेस से भी सरकार को 11,900 करोड़ रुपये मिले हैं। जीएसटी की छप्परफाड़ सफलता के बाद जब देश इसके सातवें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, तो सरकार का काम बस इतना है कि इन लाभों का फायदा उठाए और एक आधुनिक, विश्वस्तरीय, तकनीक से लैस अप्रत्यक्ष कर-व्यवस्था को बनाए रखें, जो समानता और सुविधा दे और प्रभावी भी हो।

विशेष अभियान के तहत अबतक 4,900 से अधिक जाली जीएसटी पंजीकरण रद्द किए गए

नयी दिल्ली। एजेंसी

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिकारियों ने देशभर में चलाए जा रहे अभियान के तहत अबतक 4,900 से अधिक जाली जीएसटी पंजीकरण रद्द किए हैं। इसके अलावा अभियान में ऐसे 17,000 जीएसटीआईएन की पहचान की गई है, जो मौजूद नहीं हैं। एक वरिष्ठ कर अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। अभी जीएसटी के तहत करीब 1.40 करोड़ कंपनियां या कारोबार पंजीकृत हैं। जीएसटी लागू होने से पहले पुरानी अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में यह संख्या आधी थी।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के सदस्य शशांक प्रिय ने कहा कि फर्जी पंजीकरण के खिलाफ अभियान में चार जुलाई तक फील्ड अधिकारियों ने 69,600 से अधिक जीएसटी पहचान संख्या (जीएसटीआईएन) को भौतिक सत्यापन के लिए चुना है। इनमें से 59,000 से अधिक जीएसटीआईएन सत्यापित किए जा चुके हैं और 16,989 मौजूद नहीं हैं। इन 69,600 जीएसटीआईएन में से 11,000 से अधिक जीएसटीआईएन निलंबित कर दिए गए हैं और 4,972 पंजीकरण रद्द किए गए हैं।

प्रिय ने उद्योग मंडल एसोचैम के जीएसटी राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा कि इन मामलों में 15,000 करोड़ रुपये से अधिक की कर चोरी का पता चला है, करीब 1,506 करोड़ रुपये का इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) ब्लॉक किया गया है और 87 करोड़ रुपये के कर की वसूली हुई है। जीएसटी के तहत फर्जी पंजीकरण पर अंकुश लगाने के लिए 16 मई से शुरू हुआ दो माह का विशेष अभियान 15 जुलाई को समाप्त होगा। जीएसटी के तहत फर्जी पंजीकरण एक बड़ा जोखिम है, क्योंकि धोखाधड़ी करने वाले लोग जाली बिल या इन्वॉयस जारी कर गलत तरीके से आईटीसी हासिल कर लेते हैं और सरकार को चूना लगाते हैं।

भारत आने को तैयार हुई ताइवान की सेमीकंडक्टर कंपनियां

अमेरिका का साथ मिलने से चीन से निकलेगी बाहर

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

ताइवान दुनिया के लगभग 70 फीसदी से से अधिक सेमीकंडक्टर और 90 फीसदी से अधिक सबसे एडवांस चिप्स का प्रोडक्शन करता है। जब से चीन और ताइवान में टशन शुरू हुई है, तब से इस बात की सुगबुगाहट थी कि ताइवानी कंपनियां अपने बिजनेस को चीन से जल्द समेट सकती है। इस बात को तब और हवा मिली जब अमेरिका ने ताइवान को सपोर्ट किया। अब जो खबर सामने आ रही है वो भारत के लिए काफी खुशी की है। वास्तव में ताइवानी सेमीकंडक्टर कंपनियां भारत में प्लांट लगाने के लिए स्पेस की तलाश कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर भारत भी ताइवानी सेमीकंडटर कंपनियों के लिए रेड कार्पेट बिछाने को तैयार है। अगर ऐसा होता है तो देश में लाखों नौकरियां तो जेनरेट होंगी ही साथ ही भारत दुनिया में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के मामले में दुनिया का सबसे बडा देश बनने की ओर अग्रसर हो जाएगा। आइए आपको भी बताते हैं आखिर मीडिया रिपोर्ट में किस तरह की खबरें तैर रही हैं।

मैन्युफैक्चरिंग बेस को भारत में ट्रांसफर करने पर विचार

चीन के साथ लगातार चल रहे टशन के बीच, ताइवान सरकार के टॉप पॉलिसी मेकर्स ने कहा है कि प्रमुख ताइवानी टेक कंपनियां चीनी बाजार में अपने रिस्क को कम करने के लिए अपने मैन्युफैक्चरिंग बेस को भारत में ट्रांसफर करने पर विचार कर रही हैं। ताइवान के नेशनल डेवलपमेंट डिप्टी मिनिस्टर काओ शिएन-क्यू ने कहा कि सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के निर्माण के साथ कई टेक सेक्टर्स में नई दिल्ली और ताइपे के बीच सहयोग की बहुत बड़ी गुंजाइश है। अंतरराष्ट्रीय पत्रकारों के एक समूह के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रमुख ताइवानी टेक कंपनियां ग्लोबल सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए भारत को एक अहम देश के तौर पर देख रहे हैं।

बीजिंग और वाशिंगटन के बीच बढ़ते ट्रेड वॉर और ताइवान के आसपास चीनी सेना की बढ़ती ताकत के मद्देनजर ताइवानी कंपनियां अपने प्रोडक्शन बेस को चीन से यूरोप, उत्तरी अमेरिका, अमेरिका और भारत के देशों में ट्रांसफर करने पर विचार कर रही हैं। पिछले साल अगस्त में अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पालोसी की ताइवानी यात्रा के बाद चीन और ताइवान के बीच संबंध और अधिक तनावपूर्ण हो गए हैं।

भारत रेड कार्पेट बिछाने को तैयार

भारत दुनिया की सबसे बड़ी चिप मेकर ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन के अलावा दूसरी प्रमुख ताइवानी चिप मेकर कंपनियों के लिए रेड कार्पेट बिछाने को तैयार है। जिनके ग्राहकों में दुनिया की सबसे बडी कंपनी एपल भी शामिल है। शिएन-क्यू ने कहा कि ग्लोबल सप्लाई चेन रिस्ट्रक्चरिंग और 'चीन प्लस वन' स्ट्रैटिजी के लार्जर कंटेक्स्ट के साथ, मुझे यकीन है कि हम सेमीकंडक्टर और इंफोर्मेशन और कंयूनीकेशन इंडस्ट्री के क्षेत्र में दोनों पक्षों के बीच सहयोग में तेजी देखेंगे।

भारत में बनेगा प्रोडक्शन सेंटर

पता चला है कि बड़ी संख्या में ताइवानी कंपनियां भारत में दो औद्योगिक पार्कों में प्रोडक्शन सेंटर स्थापित करने जा रही हैं, जो विशेष रूप से ताइवान के प्रमुख उद्योगों के लिए स्थापित किए जा रहे हैं। एक अधिकारी ने नाम ना प्रकाशित करने की शर्त पर कहा कि ताइवान की एक सेमीकंडक्टर कंपनी के लिए भारत में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करने के लिए बातचीत अंतिम चरण में है।

द्विपक्षीय व्यापार तेजी से बढ़ा

नई दिल्ली और ताइपे ने लगभग पांच साल पहले एक ऐतिहासिक द्विपक्षीय निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसका उद्देश्य भारत में ताइवानी निवेश की रक्षा करना है। भारत और ताइवान के बीच द्विपक्षीय व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। दोनों के बीच कारोबार 2006 में 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2021 में 8.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। त्सुन-त्जु सू ने कहा कि हाल ही में, हमने ताइवानी कंपनियों के भारत आने और ऑपरेशन का विस्तार करने के लिए नई स्पीड गति देखी है। फॉक्सकॉन का विस्तार इसका एक उदाहरण है। उप मंत्री शिएन-क्यू ने कहा कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भारत और ताइवान के बीच सहयोग की काफी गुंजाइश है।

दुनिया का 70 फीसदी सेमीकंडक्टर ताइवान का

ताइवान दुनिया के लगभग 70 फीसदी से से अधिक सेमीकंडक्टर और 90 फीसदी से अधिक सबसे एडवांस चिप्स का प्रोडक्शन करता है। जो स्मार्टफोन, कार घटकों, डेटा सेंटर, लड़ाकू जेट और एआई टेक जैसे लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के लिए जरूरी हैं। त्सुन-त्जु सू ने कहा कि ताइवान सरकार ने कहा कि वह भारत के साथ आपने ट्रेड को बढाने के लिए व्यापार समझौते पर बातचीत करने की कोशिश कर रही है। ताइवान स्थित फॉक्सकॉन, जो एपल का सबसे बड़ा सप्लायर है, तमिलनाडु में आईफोन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। कंपनी अब कर्नाटक में एक और आईफोन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित कर रही है, जिसका उत्पादन अगले साल अप्रैल तक शुरू होने की उम्मीद है।

देश में तीसरी बार पहुंची 8 फीसदी से ज्यादा बेरोजगारी दर, गांवों में सबसे ज्यादा बुरा हाल

नई दिल्ली। एजेंसी

देश में औसतन बेरोजगारी दर एक बार फिर से 8 फीसदी से ज्यादा हो गई है। इस साल बीते 6 महीनों में यह तीसरा मौका है जब देश की औसतन बेरोजगारी दर 8 फीसदी ऊपर हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण इलाकों में मौसमी बेरोजगारी के कारण इस वर्ष भारत की बेरोजगारी दर तीसरी बार 8 फीसदी से ऊपर बढ़ गई.खास बात तो ये है कि शहरी इलाकों में बेरोजगारी दर में गिरावट देखने को मिली है।

शहरी इलाकों में कम हुई बेरोजगारी

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी प्राइवेट लिमिटेड की रिपोर्ट के अनुसार जून में बेरोजगारी दर पिछले महीने के 7.68 फीसदी से बढ़कर 8.45 फीसदी हो गई। पिछले महीने जहां शहरी इलाकों में बेरोजगारी कम होकर 7.87ऱ हो गई, वहीं ग्रामीण भारत में दो साल में सबसे अधिक 8.73 फीसदी बेरोजगारी देखी गई।

जून में क्यों बढ़ जाती है बेरोजगारी

जून आम तौर पर कृषि सेक्टर के लिए एक कमज़ोर मौसम होता है, जो देश की ग्रामीण आबादी के लिए आजीविका का एक प्रमुख सोर्स है। जून में भारत के गांवों में बेरोजगारी ऐतिहासिक रूप से बढ़ जाती है क्योंकि कटाई मई में समाप्त हो जाती है और नई फसल की बुआई जुलाई में ही गति पकड़ती है जब मानसून आगे बढ़ता है।

बेरोजगारी चिंता का विषय

बढ़ती बेरोजगारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चिंता का विषय है, जो इस साल के अंत तक दस लाख सरकारी नौकरियां प्रदान करने के अपने वादे के तहत नौकरी नियुक्ति पत्र वितरित करके अपने प्रशासन की साख को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेबर मार्केट में लगातार कमजोरी, विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में जहां भारत की लगभग दो-तिहाई आबादी रहती है, 2024 के चुनावों में सबसे ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड सकता है।

शेयर बाजार में बना इतिहास

बीएससी में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप पहली बार 300 लाख करोड़ के पार

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

शेयर बाजार में बुधवार 5 जुलाई को एक नया रिकॉर्ड देखने को मिला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन पहली बार 300 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया। इसके साथ शेयर बाजार के निवेशकों की संपत्ति करीब 49,000 करोड़ रुपये बढ़ गई। इस बीच बीएसई के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स में पिछले 5 दिनों से जारी तेजी का सिलसिला आज थम गया और यह 33 अंकों की मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। हालांकि ब्रॉडर मार्केट में तेजी जारी रही। जिसके चलते मार्केट कैपिटलाइजेशन में इजाफा देखने को मिला। सबसे अधिक तेजी इश्ण्उ, ऑटोमोबाइल, ऑयल एंड गैस शेयरों में देखने को मिली। वहीं दूसरी ओर बैंकिंग और फाइनेशियल शेयरों में गिरावट का रुख रहा।

कारोबार के अंत में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सूचकांक सेंसेक्स 33.01 अंक या 0.050 फीसदी गिरकर 65,446.04 अंक पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का 50 शेयरों वाला सूचकांक निफ्टी (Nifty) 9.50 अंक या 0.05 फीसदी की तेजी के साथ 19.398.50 के स्तर पर बंद हुआ।

निवेशकों ने 49,000 करोड़ रुपये कमाए

बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट के पिटलाइजेशन 5 जुलाई को बढ़कर 300.06 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी मंगलवार 4 जुलाई को 298.57 लाख करोड़ रुपये था। इस तरह ँ ँ में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप करीब 49 हजार करोड़ रुपये बढ़ा है। या दूसरे शब्दों में कहें तो निवेशकों की वेल्थ में करीब 49 हजार करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है।

एयरपोर्ट पर रोके जाएंगे बिना पंजीकरण वाले प्लास्टिक उत्पाद

सीपीसीबी ने कस्टम विभाग को लिखा पत्र

नई दिल्ली। एजेंसी

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के विशेष पोर्टल पर पंजीकरण के लिए आवेदन नहीं करने वाली कंपनियां प्लास्टिक उत्पादों का आयात नहीं कर पाएंगी। उनके द्वारा मंगाए गए उत्पादों को हवाई अड्डे पर ही रोक लिया जाएगा। सीपीसीबी की ओर से इसके लिए कस्टम विभाग को पत्र भी लिखा गया है।जानकारी के मुताबिक एनसीआर सहित देश भर में ढेरों कंपनियां ऐसी हैं जो अपने उत्पाद प्लास्टिक की पैकेजिंग में बेचती हैं। लेकिन, इस्तेमाल के बाद यह प्लास्टिक पर्यावरण एवं नागरिक सेवाओं के लिए मुसीबत बनती है। सही तरीके से निस्तारण नहीं होने के चलते इस प्लास्टिक का एक बड़ा हिस्सा कचरे के ढेर स्वरूप वातावरण में बड़ा रहता है। वर्षा के दिनों इससे जलभराव होता है तो जाड़े के दिनों में इन्हें जलाए जाने से हवा जहरीली होती है। इस समस्या की रोकथाम के लिए ही वर्ष 2022 में जारी ई-कचरा प्रबंधन नियमों में विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसमें अपने उत्पादों को प्लास्टिक के पैकेट या रैपर में बंद करने वाली कंपनियों को भी कचरा प्रबंधन में जिम्मेदार बनाया गया है। नियमों के मुताबिक प्लास्टिक पैकेजिंग का उपयोग करने वाली कंपनियों को अपने द्वारा बेचे गए प्लास्टिक उत्पाद से पैदा हुए कचरे का बड़ा हिस्सा खुद ही एकत्रित करना होगा।

प्लास्टिक के उत्पादों के आयात पर भी अब लगाम की तैयारी

इस क्रम में सीपीसीबी द्वारा विशेष ईपीआर (एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी) पोर्टल भी बनाया गया है। पैकेजिंग से जुड़ी कंपनियों को इस पोर्टल पर पंजीकरण कराने के निर्देश दिए गए हैं। पंजीकरण नहीं कराने और पंजीकरण के लिए आवेदन तक नहीं करने वाली कंपनियों द्वारा प्लास्टिक के उत्पादों के आयात पर भी अब लगाम की तैयारी की गई है। सीपीसीबी द्वारा कस्टम विभाग को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि ईपीआर पोर्टल पर अभी तक पंजीकरण नहीं कराने

वाली कंपनियों के लिए अभी कुछ वक्त तक के लिए अंतरिम व्यवस्था की गई है। इसके मुताबिक प्लास्टिक आयात कंपनियों को इस आशय के कागजात दिखाने होंगे कि उन्होंने सीपीसीबी के ईपीआर पोर्टल में आवेदन किया हुआ है। इसके बाद ही उनके आयात को हवाई अड्डे से छोड़ा जाए। फिलहाल यह अंतरिम व्यवस्था 31 अगस्त तक के लिए की गई है। इसके बाद यह अंतरिम व्यवस्था भी खत्म हो जाएगी।

दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा विकसित एनर्जी ड्रिंक तैयार

एआई ने रेसिपी तैयार की और टेस्ट भी किया हेल एनर्जी द्वारा जल्द ही भारत में होगी उपलब्ध

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

हेल एनर्जी द्वारा दुनिया की पहली ऐसी एनर्जी ड्रिंक तैयार की गई जिसे पूरी तरह से एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) द्वारा बनाया गया है। इसकी डिज़ाइन, रेसिपी, टेस्टिंग और टेस्ट इवोल्यूशन, प्रेडिक्टिव इंटेलिजेंस, सिक्योरिटीज मीज़र्स, मार्केटिंग एलिमेंट जैसे हर पहलू को एडवांस एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) द्वारा बारीकी से तैयार किया गया है। इन्टरनेट पर मौजूद बहुत सी जानकारी और ज्ञान का उपयोग एआई द्वारा किया जाता है। यह जानकारी तेजी से को लोगों तक पहुंचाकर उनसे जुड़ सकता है। एआई एनर्जी ड्रिंक्स के बारे में इंग्रेडिएंट्स, सेल्स रिजल्ट्स, हेल्थ रिसर्च, रिकमेंडेशन और कंज्यूमर फीडबैक जैसी लगभग सारी जानकारी रखता है। इसके अलावा यह नए ट्रेंड्स और जानकारी को भी अपने एनालेसिस में सही ढंग से उपयोग कर सकता है।

जब हेल एनर्जी ने एक नई एनर्जी ड्रिंक को तैयार करने के लिए एआई को कमान सौंपी, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बहुत सारी जानकारियों को इक्कट्ठा किया और उसमें से एक सबसे अच्छी रेसिपी निकाली। एआई का उद्देश्य एनर्जी ड्रिंक उपयोगकर्ताओं की उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए एक शानदार और अच्छी एनर्जी ड्रिंक बनाना था।

वर्तमान में दुनिया की सबसे इंटेलिजेंस यूनिट एआई ने खुद की बनाई रेसिपी को परफेक्ट माना है। इस एनर्जी ड्रिंक में विटामिन, अमीनो एसिड और जड़ी बूटियों का सम्मिश्रण है। यह ड्रिंक फ़ूड इंडस्ट्री लेजिस्लेशन के अनुसार सारे सुरक्षा मानदंडों का पालन करती है, इसमें यूरोपियन फ़ूड सेफ्टी ऑथोरिटी (ईएफएसए) की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए रिकमंडेड डेली अलाउंस (आरडीए) मानकों का पालन किया गया है।

एआई ने तीन फ्लेवर वेरिएशन्स तैयार किए हैं जिनके फाइन ट्यून और डिजिटलाइज़ के लिए न्यूयॉर्क की एक कंपनी की टेक्निकल मदद ली गई। तीनों ड्रिंक्स को चखने, डेटा और आँकड़ों को एनेलाइज़ करने के बाद एआई ने अपनी प्रेडिक्टिव इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए एक शानदार स्वाद का चयन किया,और इस तरह से इस शानदार और ताजगी भरे टूटी-फ्रुट्टी एवं बेरी ब्लास्ट फ्लेवर का जन्म हुआ। यह पहली बार है जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एनर्जी ड्रिंक के क्षेत्र में इस तरह से योगदान दिया है। किसी भी रेसिपी को हमेशा गोपनीय रखा जाता है, इसे सुरक्षित रखने के लिए एआई ने सिफारिशें प्रदान की हैं। हेल एनर्जी की इस रेसिपी को हंगेरियन फैक्ट्री में एक कंप्यूटर पर इक्कठा कर रखा गया है। उस कंप्यूटर कक्ष को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा ही विकसित किया है। हालांकि, बैकअप के महत्व को समझते हुए, एक कॉपी रेसिपी को स्विट्जरलैंड में सुरक्षित रखा गया है।

नई एनर्जी ड्रिंक के पैकेजिंग को भी एआई ने ही डिज़ाइन किया है। इसकी कैन में यूथफुल कूल वाइब है, ताजगी के साथ हेल एनर्जी के कलर स्कीम शामिल करते हुए एआई ने इसकी डिजिटल स्टाइल को भी डिजाइन में शामिल किया है। 'हेल एआई' एक यूनीक प्रोसेस है, जिसकी तुलना वैश्विक स्तर पर नहीं की जा सकती। कंपनी के कर्मचारी इसकी टेस्टिंग के लिए बहुत उत्सुक थे इसलिए ड्रिंक को टफ क्वालिटी कण्ट्रोल और ब्लाइंड टेस्टिंग के दौर से गुजारा गया जिसमें यह पास भी हुआ, जो एआई की क्षमताओं को दर्शाता है।

एआई फ़ूड इंडस्ट्री के क्षेत्र में प्रोडक्ट डेवलपमेंट के एक बहुत बड़े विज़न को लेकर चलता है, जो आउट ऑफ़ द बॉक्स सोचकर फ़ूड इंडस्ट्री के नए युग की शुरुआत कर रहा है। एआई की क्षमताओं के साथ, वह इंटरनेट डेटा को कुछ मिनटों- सेकंडों में सॉर्ट और एनेलेसिस कर सकता है, जिससे प्रोडक्ट डेवलपमेंट सायकल 1-2 वर्षों से घटकर 1 महीने कम हो सकती है। यह प्रक्रिया अथक प्रयासों का परिणाम है, कई क्षेत्रों में एआई सिस्टम ने शानदार प्रदर्शन किया है, जो नए आविष्कार में और तेजी एवं बेहतरी सुनिश्चित करता है। यूरोप के सबसे शानदार ड्रिंक प्रोडक्शन यूनिट में से एक में यह नया प्रोडक्ट तैयार किया जाता है।2023 की गर्मियों के बाद से इसकी शुरुआत हो चुकी है और यह जल्द 60 से अधिक देशों में उपलब्ध होगा।

भारत का रूसी तेल आयात नए शिखर पर पहुंचा

नई दिल्ली। एजेंसी

लगातार 11वें महीने भी भारत ने रियायती दरों पर रूस से क्रूड आयल खरीदकर एक रिकॉर्ड बना लिया। जून में रूस से रिकॉर्ड मात्रा में कच्चे तेल का आयात किया गया। माना जा रहा है कि आने वाले समय में रिकॉर्ड तोड़ने का यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। क्योंकि देश प्रमुख तेल उत्पादक से अपनी खरीद की सीमा के करीब पहुंच गया था। इसके साथ ही बाजार में एक बड़ा बदलाव भी आया है। रिलायंस कंपनी को पछाड़ते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) रूस से कच्चा तेल का सबसे बड़ा खरीददार बन गया। रुसी बाजार से तेल खरीदने के लिए भारत पेट्रोलियम भी बातचीत कर रही है। डेटा एनालिटिक्स फर्म केपलर में कच्चे तेल के विश्लेषण के प्रमुख विक्टर कटोना ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि जून में दैनिक मात्रा बढ़कर 2.2 मिलियन बैरल प्रति दिन हो गई, जो लगातार 10वें महीने बढ़ रही है। रशियन शॉप एक बार फिर सऊदी अरब और इराक के यूनाइटेड शिपमेंट से अधिक हो गई। केप्लर ने इसके पहले बताया था कि मई में भारत के तेल आयात में मास्को का हिस्सा 46इ था, जो कि यूक्रेन पर आक्रमण से पहले 2इ से भी कम था। भारत ने रूसी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए आगे कदम बढ़ाया है।

भारत प्रमुख तेल उपभोक्ता के रूप में आया आगे

यूक्रेन पर आक्रमण के बाद भारत रूसी तेल के प्रमुख उपभोक्ता के रूप में उभरा है। केंद्र के स्वामित्व वाली इंडियन ऑयल पिछले दो महीनों में रूसी कच्चे तेल की सबसे बड़ी खरीदार रही है, इसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का नंबर आता है। कुल मिलाकर, भारत के यूराल आयात ने जून में प्रतिदिन 1.5 मिलियन बैरल का एक और रिकॉर्ड बनाया। भारतीय तटों पर पहुंचाए जाने वाले रूसी कच्चे तेल की औसत लागत अप्रैल में 68.21 डॉलर प्रति बैरल थी - जबकि सऊदी तेल 86.96 डॉलर थी। रुसी कच्चा तेल मई महीने में भारत ने 2.15 मिलियन बैरल प्रतिदिन और इसके पहले अप्रैल महीने में 1.9 मिलियन बैरल प्रतिदिन ख़रीदा। पिछले साल भी भारत ने रूस से कच्चे तेल की खरीदी पर मिलियन का आंकड़ा पार करके नया रिकॉर्ड बनाया था। अब भले ही मानसून आ गया जब इंधन की खपत कम हो जाती है तब भी कच्चे तेल की खरीदारी में भारत रिकॉर्ड कायम कर रहा है।

हमें कॉर्पोरेट बोर्ड में ज्यादा महिलाओं की जरूरत है : अरुंधति भट्टाचार्य

नई दिल्ली। एजेंसी

सेल्सफोर्स इंडिया की शीर्ष बॉस और एसबीआई की पूर्व चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य ने कहा है कि कॉर्पोरेट बोर्डरूम में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 'कहीं अधिक' होने की जरूरत है, और इसमें मानसिकता में बदलाव, दृढ़ कार्रवाई और फोकस शामिल होगा।

भट्टाचार्य ने भारतीय व्यवसाइयों को कुछ ज़रूरी सलाह देते हुए कहा कि उन्हें डिजिटल परिवर्तन को 'जरूरी' के रूप में देखने की जरूरत है, न कि केवल कुछ अच्छी चीज के रूप में। उन्होंने वकालत की कि ऐसे संगठन जिनके पास बेहतर काम के तरीके नहीं हैं , साइलो और मैन्युअल प्रक्रियाओं में डेटा रहता है, या कौशल की कमी है, वे तब तक पिछड़ जाएंगे, जब तक वे तकनीक और डिजिटल को नहीं अपनाते। उन्होंने कहा कि हर एक क्षेत्र - चाहे वह स्वास्थ्य सेवा हो, ऑटोमोटिव हो या विनिर्माण हो, सेल्सफोर्स के लिए एक अवसर प्रस्तुत करता है।

महिलाओं के सवाल जो उनके दिल के बहुत क़रीब हैं उन पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि सामान्य परिस्थिति फिर से शुरू होने के बाद महिलाओं को काम पर वापस लाने के लिए कोई एक तरीका सभी के लिए काम नहीं कर सकता, उन्होंने कहा इस बारे में हमें लचीलेपन का रुख इस्तेमाल करना चाहिए। इस संबंध में उनकी चिंता महत्वपूर्ण है क्योंकि उद्योग जगत की चिंताएं रही हैं कि घर से काम की समाप्ति से कुछ मामलों में महिला श्रमिकों के बीच उद्योग में गिरावट आ सकती है।

इस बात को और मज़बूती से उठाते हुए भारत की सबसे बड़ी तकनीकी कंपनी टीसीएस का एक बयान महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसकी महिला कर्मचारियों के बीच नौकरी छोड़ने की दर पुरुषों की तुलना में अधिक हो गई है, यह संकेत देते हुए कि घर से काम की समाप्ति की इसमें भूमिका हो सकती है। भट्टाचार्य ने कॉरपोरेट बोर्डरूम में महिलाओं के अधिक प्रतिनिधित्व की भी वकालत की। उन्होंने कहा, कॉरपोरेट बोर्डरूम में कहीं अधिक महिलाओं की जरूरत है। मुझे लगता है कि यह मानसिकता बदलने का सवाल है.' उन्होंने सी-सूट (यानी किसी संस्थान में सबसे ज्यादा रैंकिंग वाले वरिष्ठ अधिकारी) के अधिकारियों की बाद में बोर्डरूम की ओर प्रगति की ओर इशारा किया और महसूस किया कि चूंकि सी-सूट में महिलाओं की संख्या सीमित है, इसलिए यह अंततः बोर्डरूम में समग्र प्रतिनिधित्व को भी प्रतिबिंबित करती है।

जीएसटी नंबर लेने के साथ होगी बिल्डिंग की जियो टैगिंग

डमी कंपनियों और फर्जीवाड़े पर लगेगी रोक

पंचकूला । एजेंसी

हरियाणा में जीएसटी के अंदर अब फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के निर्देश पर राज्य सरकार ने जीएसटी नंबर लेने वालों की बिल्डिंग व उनके पते की जियो टैगिंग का काम शुरू कर दिया है। पंचकूला में जियो टैगिंग का काम शुरू किया जा चुका है। अब इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। जीएसटी विशेषज्ञ ने बताया कि इससे डमी कंपनियों व फर्जी जीएसटी नंबर पकड़ में आएगा और सरकार को चपत लगा रहे लोग आसानी से गिरफ्त में आएंगे।जीएसटी नंबर लेने के बाद जब एड्रेस की जियो टैगिंग होगी तो इससे पता चल जाएगा कि उस मकान या बिल्डिंग के पते पर कितने जीएसटी नंबर है। यदि किसी ने पहले से ही उस एड्रेस पर जीएसटी नंबर लिया है तो उसका ब्योरा पोर्टल में दिखने लगेगा। इससे फर्जीवाड़ा पकड़ में आ जाएगा और राजस्व को नुकसान से बचाया जा सकेगा। चौटाला ने बताया कि पंचकूला देश का पहला शहर है, जहां जीएसटी नंबर के साथ जियो टैगिंग की जा रही है। वहीं, सीबीआईसी के मुताबिक दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में कई फर्जी कंपनियां हैं। इसमें ज्यादातर कारोबारी मेटल, प्लास्टिक स्क्रैप और रद्दी कागज वाले कारोबारी हैं। जीएसटी विशेषज्ञ ने बताया कि ध्यान देने वाली बात यह है कि जियोकोडर पते के विवरण को अपडेट करने से करदाता के खाते से जुड़े किसी भी मौजूदा पते में कोई बदलाव नहीं आएगा।

भारत से पहले इन देशों ने अपनाया

भारत से पहले जियोकोडिंग को संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और ब्राजील ने अपनाया है, जहां यह प्रयोग पूरी तरह से सफल रहा है। इस सुविधा का उद्देश्य जीएसटी रिकॉर्ड में पत्ते के विवरण की सटीकता सुनिश्चित और पता स्थान और सत्यापन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है।

क्या होती है जियो टैगिंग

डिजिटल युग में जियो टैगिंग का काफी महत्व है। जियो टैगिंग का मतलब किसी भी काम की भौगोलिक स्थिति, फोटो, मैप और वीडियो के जरिए सटीक जानकारी देना है। इनका मुख्य उद्देश्य लोकेशन की सटीक जानकारी देना होता है।

सावन में भगवान भोलेनाथ को धतूरे चढ़ाने से भर जाएगी खाली झोली

हिंदू धर्म में सावन के महीने को बहुत पवित्र माना जाता है। इस दौरान भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भक्त सावन सोमवार का व्रत रखते हैं! इसके साथ ही भगवान शिव के भक्त कई चीजें चढ़ाते हैं। जिससे खुश होकर शिवजी भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। इस बार सावन 4 जुलाई से शुरु हो चुका है। शिव जी पर बेलपत्र सबसे ज्यादा चढ़ाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह और कौन-से फूल-पत्ते हैं जो शिव जी को अति प्रिय हैं, लेकिन धतूरा भी शिवजी को बेहद प्रिय है। सावन के महीने में भगवान शिव को धतूरा चढ़ाने से भी वह जल्द प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही धतूरे के कुछ उपाय करके भी शिवजी की कृपा पा सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सावन सोमवार के दिन धतूरे की जड़ को घर में स्थापित करें। इसके बाद मां काली की पूजा करके उनके बीज मंत्र का 108 बार जाप करें. इससे धन सबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं।

डॉ. संतोष वाधवानी
रत्न एवं वास्तु विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष एवं वास्तु एसोसिएशन प्रदेश प्रवक्ता

संतान की प्राप्ति के लिए

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सावन के महीने में धतूरा का फल शिवलिंग पर अर्पित करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है।

संकट दूर करने के लिए

शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने में अश्लेषा नक्षत्र में धतूरे की जड़ को घर में लाकर स्थापित कर दें. कहते हैं इससे घर में आने वाला संकट टल जाएगा।

बुरी शक्तियों से बचाव के लिए

शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने में काले धतूरे की जड़ को रविवार या मंगलवार के दिन घर में स्थापित करने से बुरी शक्तियां आसपास भी नहीं भटकती. साथ ही घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है।

सभी परेशानी से मुक्ति के लिए

शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने में सावन सोमवार के दिन अगर कोई व्यक्ति धतूरे की जड़ को अपने बाएं हाथ की कलाई में बांध लें तो उसके जीवन में आ रही सभी परेशानियां दूर हो जाती है।

धन हानि नहीं होगी

शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने में शिवजी पर चढ़े धतूरे को घर की तिजोरी में रखने से धन हानि का सामना नहीं करना पड़ता।

नकारात्मक ऊर्जा होगी दूर

शास्त्रों के अनुसार धतूरा घर के मुख्य द्वार पर लटकाने से घर में कभी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती. ध्यान रखें कि इसे सूखने से बाद बदलते रहें।

भगवान शिव को ये चीजें करें अर्पित, सालभर रहेगी महादेव-मां पार्वती की कृपा

डॉ. आर.डी. आचार्य
9009369396
ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
इंदौर (म.प्र.)

सावन का पवित्र महीना प्रारंभ हो गया है। सावन का महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग इस महीने में पूरी श्रद्धा से भोलेनाथ की सेवा करते हैं उन्हें शुभ फल मिलता है। भोलेनाथ को प्रसन्न करना बहुत ही सरल है। इस माह रुद्राभिषेक करने से भगवान शिव को प्रसन्न किया जा सकता है। जल चढ़ाने के बाद भक्त भगवान भोलेनाथ को भोग के रूप में बेलपत्र, शमी के पत्ते, कुशा, दूब, भांग, धतूरा और श्रीफल चढ़ाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति इस महीने में पूरे विधि-विधान से भगवान शिव की पूजा करता है, तो उसे सभी प्रकार के दुखों, चिंताओं और परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। जानें भगवान शिव को नीचे बताई गई चीजें अर्पित करने से लोगों को क्या लाभ मिलता है।

सुख-समृद्धि पाने के लिए शिवलिंग पर चढ़ाएं ये चीजें-

1. सावन के सोमवार के दिन यदि आप किसी तीर्थ या गंगा नदी से निकले जल से शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं तो ऐसे लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है।

2. शिवलिंग पर लगातार जल चढ़ाने से परिवार में सुख-शांति बनी रहती है और बीमारियां दूर होती हैं।

3. अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से कमजोर, थका हुआ और बीमार महसूस करता है तो उसे शिवलिंग पर गाय के दूध से बना शुद्ध घी चढ़ाना चाहिए, ऐसा करने से मानसिक और शारीरिक शक्ति बढ़ती है।

4. शिवलिंग पर दही चढ़ाने से लोगों को सभी प्रकार की धन-संपत्ति प्राप्त होती है और परिवार में खुशहाली बनी रहती है। भगवान शिव को कुशा का जल या सुगंधित इत्र आदि चढ़ाने से सभी रोग और दोष दूर हो जाते हैं।

5. अगर सोमवार के दिन भगवान शिव को गन्ने का रस अर्पित किया जाए तो मां लक्ष्मी अपार कृपा और सांसारिक सुख प्रदान करती हैं।

6. शिवलिंग पर दूध-चीनी मिश्रित जल चढ़ाने से अच्छी बुद्धि मिलती है, बच्चों का दिमाग तेज होता है और वे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं।

7. शिवलिंग पर शमी के पत्ते चढ़ाने से शनि ग्रह के दुष्प्रभाव से मुक्ति मिलती है। लेकिन यह सलाह केवल उन्हीं लोगों को अपनानी चाहिए जिनकी कुंडली में शनि ग्रह नीच स्थिति में है और उसके बुरे प्रभाव से पीड़ित है।

8. भगवान शिव को गेहूं चढ़ाने से सुयोग्य और आज्ञाकारी पुत्र की प्राप्ति होती है और वंश में वृद्धि होती है। घर के सदस्यों के बीच संबंधों में मधुरता आती है।

9. सोमवार के दिन भोलेनाथ को जौ चढ़ाने से कष्ट दूर होते हैं और तिल चढ़ाने से पापों का नाश होता है। ऐसा करने से लोगों को न सिर्फ मानसिक खुशी मिलती है बल्कि सामाजिक स्तर पर भी सफलता मिलती है।

10. शिवलिंग पर अक्षत चढ़ाने से जातक धन-धान्य से भर जाते हैं। ऐसे लोगों को किसी भी चीज की कमी नहीं होती और वे सुखी जीवन जीते हैं।

मंगल और गुरु के संयोग से बना नवपंचम योग

इन 4 राशि वालों को धन लाभ और तरक्की के योग

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी कोई ग्रह गोचर करता है या फिर दो ग्रहों की युति बनती है तो कई तरह के शुभ और अशुभ योगों का निर्माण होता है। इस समय मंगल और देवगुरु बृहस्पति के संयोग से नवपंचम योग का निर्माण हुआ है। गौरतलब है कि मंगल ग्रह 1 जुलाई से अपनी राशि कर्क की यात्रा को समाप्त करते हुए सिंह राशि में प्रवेश किया है। कर्क राशि मंगल की नीच की राशि मानी गई हैं। नवपंचम योग गुरु और मंगल ग्रह के योग से मिलकर बना होता है। इस शुभ योग के बनने से 4 राशि के जातकों को धन लाभ और सफलता प्राप्त के योग बन रहे हैं। आइए जानते हैं कौन-कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिनको इसका लाभ मिल सकता है।

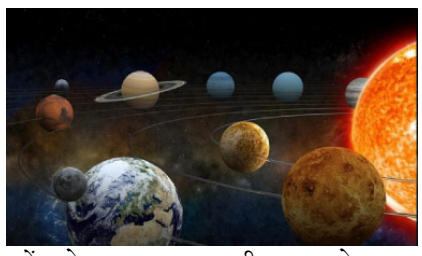

मेष राशि : मेष राशि के जातकों के लिए नवपंचम योग बहुत ही शुभ साबित होने जा रहा है। ज्योतिषीय गणना के मुताबिक इस समय मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति और सिंह राशि में सूर्य हैं जिससे गुरु की दृष्टि मंगल पर है। ऐसे में मेष राशि के जातकों के मान-सम्मान में वृद्धि हो सकती है। कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। नौकरी में सफलता पाने के लिए आने वाले समय बहुत ही अच्छा हो सकता है। प्रभावशाली लोगों से आपका मेल-मिलाप हो सकता है।

कर्क राशि : कर्क राशि के जातकों के लिए नवपंचम योग किसी वरदान से कम नहीं है। आपको अचानक से धन लाभ की संभावना है। लेन-देन के मामलों में आपकी जीत होगी। किसी तरह की खरीदारी आपके लिए शुभ साबित होगी। नौकरीपेशा जातकों को लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आप धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं।

सिंह राशि : गुरु और मंगल के योग से नवपंचम योग बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो सकता है। सिंह राशि में मंगल हमेशा से ही योग कारक होते हैं। गुरु भाग्य स्थान से मंगलदेव पर दृष्टि रख रहे हैं ऐसे में यह समय आपके लिए भाग्य में वृद्धि का हो सकता है। अधूरे कार्यों में आपको सफलता हासिल हो सकती है। व्यापार में अच्छा मुनाफा होने के योग बन रहे हैं। इस शुभ योग से छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में कई तरह के बेहतरीन सफलता मिल सकती है।

श्री रोशनी शर्मा
9265235662
हस्त रेखा एवं फेस रीडर (ज्योतिषाचार्य)

तुला राशि : करियर और व्यापार के नजरिए से नवपंचम योग बहुत ही शुभ साबित होने वाला है। आपकी इनकम में अच्छा इजाफा देखने को मिलेगा। जीवनसाथी का भरपूर साथ मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। आपके द्वारा बनाई गई योजना में आपको सफलता हासिल होगी। उधार दिया हुआ धन जल्द वापस मिलने की संभावना है।

बैंबू प्लांट करता है मन शांत युवाओं की बढ़ी दिलचस्पी

भागदौड़ भरी जिंदगी में आज हर व्यक्ति तनाव में है। युवा भी इसकी चपेट में हैं। हर कोई सुख-समृद्धि और शांति चाहता है। ऐसे में बैंबू प्लांट संकट मोचन से कम नहीं है। मन मस्तिष्क को शांत रखने के साथ घर-आफिस में एक सकारात्मक माहौल भी तैयार करता है। वास्तु शास्त्र में बैंबू प्लांट (बांस का पौधा) को शुभ माना जाता है।

वास्तु विशेषज्ञ वासुदेव शर्मा के मुताबिक हमारे जीवन में घर को सजाने और सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए वास्तु शास्त्र का बहुत अहम योगदान होता है। ऐसा माना जाता है कि यदि आपके घर में हर एक चीज को वास्तु के नियमों के अनुसार रखा जाए तो वो खुशहाली लेकर आती है। वहीं घर में पेड़-पौधे रखने की भी वास्तु के अनुसार एक निश्चित जगह बताई गई है। मिनी बैंबू प्लांट यह वह पौधा है जिसमें ढेरों खूबियां हैं। सजावट के साथ ये व्यक्ति के सोई हुई किस्मत का ताला भी खोल सकता है। यही कारण है कि अब युवा भी इसकी ओर आकर्षित होने लगे हैं। ज्यादातर कालेज स्टूडेंट का मानना है कि इस पौधे को देखने मात्र से मन में एक पाजिटीविटी का अहसास होता है। हरियाली इतनी प्यारी होती है कि मन को शांति महसूस होने लगती है।

टमाटर के बाद अब मसाले हुए गर्म

आसमान पर पहुंचे भाव

नई दिल्ली। हर घर की रसोई में मौजूद मसालेदानी के मसालों के दाम इतने बढ़ गए हैं कि आम आदमी के पसीने छूटने लगे हैं। जीरे और हल्दी में 24 प्रतिशत की बढ़ोतरी ने सब्जियों में इसके इस्तेमाल पर हाथ तंग होता दिखाई देने लगा है। एक्सपोर्ट और मजबूत घरेलू डिमांड के चलते जीरा 56000 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गया है। जीरे का उत्पादन करने वाले दो मुख्य राज्य गुजरात और राजस्थान में मार्च महीने में हुई बेमौसम बारिश के बाद पैदावार में हुई गिरावट से जीरे के दामों में यह बढ़ोतरी लगातार जारी है।

राजस्थान मंडी के कमोडिटी एक्सपर्ट पुखराज चोपड़ा कहते हैं, 'बेमौसम बारिश और बिपरजॉय तूफान के ओलों ने खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाया है। यहां अच्छी जीरा बुआई के कारण 75 लाख बोरी फसल की जगह अब 50-52 लाख बोरी ही हाथ में आने का अनुमान है। इसका फायदा मसालों का स्टॉक करने वाले उठाते हैं और भाव आसमान पहुंचने लगते हैं।' केडिया कमोडिटी के सीईओ अजय केडिया का कहना है कि पिछले एक महीने में मसालों के दामों में तेजी आई है। सप्लाई में बाधा, बेमौसम बारिश, बिपरजॉय तूफान और जीरे में 23.55 %, हल्दी में 23.62%, धनिया 16%, लाल मिर्च 14%, सौंठ में 8% तक दामों की बढ़ोतरी हो चुकी है और आगे भी तेजी रहने की आशंका है।'

अदरक और सौंठ भी महंगा

इधर अदरक और सौंठ के दाम भी आसमान छू रहे हैं, जिसकी वजह से चाय और सब्जियों का जायका प्रभावित हुआ है। माटुंगा निवासी रंजना कुलकर्णी कहती हैं, 'सरकार कहती है कि रिटेल महंगाई घटकर 4.25 पर्सेंट रह गई है, लेकिन रसोई का बजट पूरी तरह बिगड़ गया है। 100 ग्राम अदरक 40 रुपये में मिल रही है। मिर्च भी महंगी हो गई है। टमाटर तो पहले ही 150 रुपये किलो हैं। हमने इनका इस्तेमाल बंद कर दिया है। एपीएमसी सेक्रेटरी अनिल चव्हाण का कहना है कि अदरक के 325 रुपये प्रति किलो तक पहुंचने की वजह कर्नाटक में हुई बेमौसम बारिश और मणिपुर में चल रहे तनाव से इसकी सप्लाई का कम होना है।

भारत की नई ड्रोन नीति

जल्दी ही आम आदमी भी उड़ाएगा ड्रोन

नई दिल्ली। एजेंसी

भारत सरकार ने नागरिक उपयोग के लिए ड्रोन और मानव रहित हवाई वाहन की निर्यात नीति को और सरल तथा उदार बना दिया है। सभी प्रकार के ड्रोन और यूएवी विशेष रसायन जीव सामग्री उपकरण और प्रौद्योगिकी (SCOMET) सूची की श्रेणी 5 (B) के तहत निर्यात के लिए प्रतिबंधित किए गए थे, अब उनके नागरिक और सैन्य दोनों तरह के इस्तेमाल हो सकते हैं।

डीजीएफटी ने कहा, ऐसी वस्तुओं के निर्यात के लिए पहले स्कोमेट लाइसेंस की ज़रुरत थी, और उद्योग को सीमित क्षमता वाले ड्रोन निर्यात करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, अब नागरिक उपयोग के लिए ड्रोन और यूएवी की स्कोमेट नीति में संशोधन किया गया है। इस नीति परिवर्तन से जीएईडी प्राधिकरण वाले ड्रोन निर्माताओं और निर्यातकों को पोस्ट रिपोर्टिंग और अन्य दस्तावेजी आवश्यकताओं के अधीन तीन साल की वैधता अवधि के भीतर नागरिक उद्देश्य के लिए प्रत्येक समान निर्यात शिपमेंट के लिए स्कोमेट लाइसेंस के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी, डीजीएफटी के अनुसार उद्योग को हर बार किसी भी प्रकार के नागरिक ड्रोन का निर्यात करने के लिए स्कोमेट लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा।

इससे यूएवी उद्योग को आसानी से ड्रोन निर्यात करने में सुविधा होगी, जिससे व्यापार करने में आसानी होगी और भारत से निर्यात को बढ़ावा मिलेगा,' इसमें कहा गया है कि यह इस क्षेत्र में स्टार्ट-अप और नए ड्रोन निर्माताओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। यह भी कहा गया है कि वैश्विक बाजारों पर नज़र डालें, भारतीय ड्रोन निर्माताओं को बड़े बाज़ारों तक पहुँचने की अनुमति दें, और उद्योग में नवाचार को प्रोत्साहित करें. इससे बड़े परिवर्तन देखे जा सकते हैं।

इसी महीने टाटा की कारें होंगी महंगी

नई दिल्ली। एजेंसी

अगर आप टाटा की कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो अब आपकी जेब और ढीली हो सकती है। दरअसल टाटा मोटर्स अपनी कारों के रेट बढ़ाने जा रही है। इस महीने यानी 17 जुलाई 2023 से टाटा की कारें महंगी हो जाएंगी। ऐसे में लोगों को टाटा की कार खरीदने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ जाएंगे। कंपनी ने एक बयान में कहा कि 17 जुलाई से उसकी कारें महंगी हो जाएंगी। कंपनी के मुताबिक, पैसेंजर व्हीकल की नई कीमत 17 जुलाई 2023 से लागू होंगी। सभी मॉडल्स और वेरिएंट्स की कीमत में औसत 0.6 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। कंपनी ने कहा है कि टाटा मोटर्स 16 जुलाई 2023 तक की गई बुकिंग और 31 जुलाई 2023 तक की डिलीवरी पर प्राइस प्रोटेक्शन प्रदान करेगी। बता दें कि इससे पहले मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी बाइक और स्कूटर के दाम 3 जुलाई से बढ़ाने का ऐलान किया था। टाटा मोटर्स के मुताबिक, पिछली इनपुट लागतों के प्रभाव की भरपाई के लिए गाड़ियों की कीमत बढ़ाई गई है। टाटा मोटर्स की गाड़ियों की सेल में भी इजाफा देखने को मिला है। बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक, बीते जून महीने में टाटा मोटर्स की गाड़ियों की जमकर बिक्री हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जून में टाटा मोटर्स की कुल घरेलू बिक्री सालाना आधार पर एक फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 80,383 इकाई हो गई है। जून 2022 में कंपनी ने 79606 वाहनों की बिक्री की थी।

50 से अधिक उम्र में मोतियाबिंद का खतरा

एल्कॉन आइ ऑन कैरेक्टर सर्वे के नतीजों का खुलासा

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

आंखों की देखभाल के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर एल्कॉन ने अपने महत्वपूर्ण एल्कॉन आइ ऑन कैटरेक्ट सर्वे के नतीजों का खुलासा किया। यह सर्वे मार्च-अप्रैल 2023 के दौरान भारत समेत दुनिया के 10 देशों में 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के बीच, विजन और कैटरेक्ट संबंधी पड़ताल के उद्देश्य से कराया गया है। इस सर्वे में उन लोगों को शामिल किया गया था जिनमें पिछले पांच वर्षों में मोतियाबिंद की पुष्टि हुई थी और जो मोतियाबिंद सर्जरी का इंतजार कर रहे थे अथवा करवा चुके थे इसमें 50 वर्ष से ऊपर के ऐसे लोग भी शामिल थे जिन्हें कैटरेक्ट की शिकायत नहीं थी इस सर्वे से यह स्पष्ट हुआ कि जो मरीज कैटरेक्ट सर्जरी करवा चुके हैं उनकी आंखों में और जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।

एल्कॉन इंडिया के कंट्री मैनेजर अमर व्यास ने कहा हम दुनियाभर में जून माह के दौरान मनाए गए मोतियाबिंद जागरूकता माह के मद्देनजर इस सर्वे के नतीजों को साझा करते हुए खुशी महसूस कर रहे हैं इस सर्वे ने इस बारे में और जागरूकता बढाने की जरूरत को रेखांकित किया है। भारत में बूढ़े हो रहे वयस्कों की आबादी 260 मिलियन है। यह जानना जरूरी है कि इस सर्वे के अनुसार, जैसे-जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है स्वस्थ दृष्टि का मोल भी उतना ही बढ़ता है रोजमर्रा की गतिविधियों के लिए स्पष्ट दृष्टि का महत्व लोगों को और भी समझ आता है और सच तो यह है कि अच्छी विजन होना हैल्दी एजिंग की प्रक्रिया के लिहाज से अहम् है इस सर्वे के नतीजों ने लोगों को कैटरेक्ट सर्जरी के बाद स्पष्ट विजन के अपने विकल्पों के बारे में शिक्षित करने की जरूरत पर जोर दिया है कैटरेक्ट सर्जरी में मरीजों के धुंधलाते लैंसों को बदलकर एडवांस टैक्नोलॉजी वाले इंट्राऑक्यूलर लैंसों को लगाया जाता है। यह जीवन में एक बार की जाने वाली ऐसी सर्जरी है जो न सिर्फ कैटरेक्ट पूर्व विजन को वापस लाती है बल्कि कई रिफ्रेक्टिव दोषों जैसे प्रेसबायोपिया और एस्टिगमेटिज्म को भी ठीक कर चश्मा लगाने की जरूरत कम करती है।

जीएसटी इनपुट क्रेडिट के मिस्मेच की समस्या के संबंध में जीएसटी काउंसिल को सुझाव प्रेषित

(व्यापारियों को आ रही दिक्कतों के संबंध में सुझाव)

इंदौर। सांसद प्रतिनिधि डॉ संतोष वाधवानी ने जानकारी देते हुए बताया कि जीएसटी में सरकार द्वारा बनाई गई व्यवस्था के तहत ही एक खरीददार अपना माल या सेवा का क्रय करते समय विक्रेता को कर का भुगतान करता है और ऐसे में विक्रेता से कोई भूल हो जाए या वह कर ना चुकाए अथवा अपना रिटर्न ना भरे या किन्ही कारणों से ना भर पाए तो इसके जो भी परिणाम हो उस पर क्रेता का कोई अधिकार नहीं होता है लेकिन यदि ऐसे में क्रेता के इनपुट क्रेडिट रोक दी जाये तो यह क्रेता को बिना उसकी कोई गलती के दिया हुआ दंड होता है , ऐसे में जीएसटी काउंसिल एवं केंद्र सरकार से अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में जो कोई भी प्रक्रिया हो वह क्रेता की जगह विक्रेता पर लागू की जाए।

धारा 16 और नियम 36 पर विचार किया जावे

इसके अतिरिक्त जीएसटी के मूल स्वरुप में यह था कि क्रेता से उसकी खरीद की सूचना ली जाए और उसे विक्रेता द्वारा दी गई बिक्री की सुचना से मिलाया जाए और आने वाले फर्क के लिए विक्रेता को पाबन्द किया जाए लेकिन यह व्यवस्था प्रारम्भ ही नहीं की गई इसीलिये जीएसटी इनपुट की बहुत सी समस्याएं खड़ी हो रही है।जीएसटी में कर चोरी को रोकने के सरकार के प्रयास सराहनीय है और हमेशा इन क़दमों एवं प्रयासों की प्रशंसा की जानी चाहिए लेकिन जीएसटी कानून की धारा 16(4) एवं नियम 36 (4) एवं कई अन्य प्रावधान ऐसे है 'गलती और विलम्ब' तथा कर चोरी के बीच के अंतर को ही मिटा दिया है । तकनीकी गलतियों के भी डीलर्स को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं।

अब पैन और आधार का नहीं हो पाएगा गलत इस्तेमाल

सरकार लाने जा रही डेटा प्रोटेक्शन बिल

नई दिल्ली। एजेंसी

केंद्र सरकार पहचान की चोरी पर रोक लगाने और पेन और आधार के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्ती बढ़ाने की तैयारी में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फर्मेशन टेक्नॉलजी मंत्रालय को प्रस्तावित डेटा प्रोटेक्शन बिल में पेनल्टी और सजा में पर्याप्त इजाफा करने का प्रस्ताव दिया है। इस बिल को संसद के मॉनसून सत्र में पेश किए जाने की संभावना है। वित्त मंत्रालय के एक सीनियर अफसर ने कहा, 'PAN और आधार के दुरुपयोग पर पेनल्टी बहुत कम है। चूंकि इनके दुरुपयोग से केंद्र और राज्य दोनों को रेवेन्यू का अच्छा खासा नुकसान हो रहा है लिहाजा ढांचे को सख्त करने की जरूरत है।' फिलहाल, PAN के दुरुपयोग पर 10,000 रुपये का जुर्माना या छह महीने की कैद हो सकती है। सरकार ने यह कदम तब उठाया जब पता चला कि फर्जी कंपनियों को चोरी की पहचान का उपयोग करके रजिस्टर कराया जा रहा है।

टेक्नोलॉजी करेगी मदद

अधिकारी ने कहा, 'यह बहुत चिंता का विषय है और ऐसे समय पर जब टेक्नॉलजी हमें इसे रोकने में मदद कर रही है तब दोषियों को रोकने के लिए ज्यादा पेनल्टी लगाए जाने की जरूरत है और हमने अपनी ओर से मजबूत सिफारिशें भेजी हैं। यह सिफारिश पिछले महीने की गई हैं।' फर्जी रजिस्ट्रेशन के खिलाफ चल रहे अभियान में GST अधिकारियों ने पूरे भारत में ऐसे 12,000 फर्जी संस्थाओं को ट्रैक किया, जिससे सरकारी खजाने को अनुमानित तौर 30,000 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व नुकसान हुआ है।

ये है तैयारी

बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) देश भर में GST-रजिस्टर्ट फर्मों के बायोमेट्रिक सत्यापन और जियोटैगिंग करने को लागू करने की योजना बना रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फर्मेशन टेक्नॉलजी मंत्रालय पहले से ही संशोधित ड्राफ्ट कानून पर काम कर रहा है और स्टेकहोल्डरों के साथ परामर्श का एक नया दौर शुरू किया है। अधिकारी ने कहा कि इसे दुरुस्त करने के बाद मंजूरी के लिए कैबिनेट में ले जाया जाएगा।

रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण की दिशा में RBI का बड़ा कदम

इंटर-डिपार्टमेंटल ग्रुप के रिपोर्ट का करेगी अध्ययन

नई दिल्ली।आईपीटी नेटवर्क

भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि भारतीय करेंसी रुपये के अंतराष्ट्रीयकरण को लेकर इंटर-डिपार्टमेंटल ग्रुप की रिपोर्ट का वो अध्ययन करेगी। आरबीआई ने रिपोर्ट को अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। हालांकि आरबीआई ने रुपये के अंतराष्ट्रीयकरण को लेकर रिपोर्ट में कही गई बातें और सुझाव को इंटर-डिपार्टमेंटल ग्रुप की अपनी राय बताया है। आरबीआई का कहना है कि इस रिपोर्ट के साथ आधिकारिक तौर कोई लेना-देना नहीं है।

आरबीआई ने रुपये के अंतराष्ट्रीयकरण पर विचार करने के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राधा श्याम राठो की अध्यक्षता में इंटर-डिपार्टमेंटल ग्रुप का गठन किया था। इस ग्रुप के गठन का मकसद इंटरनेशनल करेंसी के रूप में रुपये के स्थान का पता लगाने के साथ ही रुपये के अंतराष्ट्रीयकरण का रोडमैप तैयार करना था। इंटर-डिपार्टमेंटल ग्रुप में अपने आखिरी सुझावों वाले रिपोर्ट को सबमिट कर दिया है।

रुपये के अंतराष्ट्रीयकरण पर इंटर-डिपार्टमेंटल ग्रुप के सुझावों के देखें को कमिटी ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय ट्रेड के लिए इनवॉयसिंग, सेटलमेंट और पेमेंट को रुपये और स्थानीय करेंसी में किए जाने का सुझाव दिया है। कमिटी ने मौजूदा बहुपक्षीय मैकेनिज्म जैसे एसीयू में रुपये को एडिशनल सेटलमेंट करेंसी के रूप में स्थापित करने का सुझाव दिया है। साथ द्विपक्षीय ट्रांजैक्शन में स्थानीय करेंसी के अलावा काउंटरपार्ट्स देशों के साथ स्थानीय करेंसी में ट्रेड को बढ़ावा देने की सिफारिश की है।

इंटर-डिपार्टमेंटल ग्रुप ने भारत या विदेश में नॉन-रेसिडेंट्स के लिए रुपये अकाउंट्स खोलने को बढ़ाना देने का सुझाव दिया है। क्रॉस बार्डर ट्रांजैक्शन के लिए इंडियन पेमेंट सिस्टम को इंटीग्रेट करने का भी सुझाव दिया गया है। कमिटी ने ग्लोबल 24ङ5 रुपये मार्केट को बढ़ावा देने के लिए फाइनैंशियल मार्केट को मजबूत किए जाने पर जोर दिया है साथ ही भारत को रुपये ट्रांजैक्शन का हब बनाने को बढ़ावा देने और बेहतर प्राइस डिस्कवरी के रूप में स्थापित किए जाने का सुझाव दिया है. एक्सपोर्टर्स को रुपये में ट्रेड सेटलमेंट करने पर इंसेटिव देने का सुझाव दिया गया है।

कमिटी ने मध्यम अवधि में मसाला बॉन्ड्स पर टैक्स की समीक्षा करने का सुझाव दिया है। क्रॉस बार्डर ट्रेड ट्रांजैक्शन के लिए आरटीजीएस के इंटरनेशनल इस्तेमाल करने और रुपये सीएलएस सिस्टम में रुपये को डायरेक्ट सेटलमेंट करेंसी में शामिल किए जाने का सुझाव दिया है। साथ ही कमिटी ने विदेशों में भारतीय बैंकों के ऑफ-शोर शाखाओं में रुपये में बैंकिंग सर्विसेज उपलब्ध कराने की सिफारिश की है।

2000 के नोटों पर आरबीआई का बड़ा ऐलान, 76 प्रतिशत नोट वापस आए

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में 2000 रुपये के नोटों को वापस लेने का ऐलान किया था। इसके बाद अब आरबीआई ने इस पर अपडेट जारी किया है। आरबीआई ने कहा कि चलन में मौजूद 2,000 रुपये के नोट वापस लेने के फैसले के बाद से 76 प्रतिशत नोट यानी 2.72 लाख करोड़ रुपये के नोट बैंकों में वापस आ गए हैं। इनमें से ज्यादातर नोट लोगों ने अपने बैंक खाते में जमा कराए हैं।

बैंकिंग

केंद्रीय बैंक ने 19 मई, 2023 को अचानक से 2,000 रुपये के नोट को वापस लेने का निर्णय किया था। लोगों से बैंक जाकर 30 सितंबर तक 2,000 रुपये के नोट अपने खातों में जमा करने या दूसरे मूल्य के नोट से बदलने को कहा गया है। रिजर्व बैंक के अनुसार, मूल्य के हिसाब से मार्च, 2023 में कुल 3.62 लाख करोड़ रुपये के नोट 2,000 रुपये के थे। यह 19 मई, 2023 को कारोबारी समय खत्म होने के बाद घटकर 3.56 लाख करोड़ रुपये रह गया था।

रिजर्व बैंक

रिजर्व बैंक ने बयान में कहा, "बैंकों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, 19 मई को 2,000 रुपये के नोट चलन से हटाने के निर्णय के बाद से 30 जून, 2023 तक 76 प्रतिशत यानी 2.72 लाख करोड़ रुपये के नोट वापस आ गये हैं।बयान के अनुसार, "इसके परिणामस्वरूप 30 जून को कारोबारी समय समाप्त होने के बाद चलन में 84 हजार करोड़ रुपये के 2,000 के नोट रह गये थे।

लघु श्रेणी फुटवियर उद्योगों पर बीआईएस की अनिवार्यता

फुटवियर उद्योग खतरे में

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

चाईना से आने वाले फूटवियर पर गुणवत्ता नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार द्वारा जनवरी 2024 से बीआईएस नियमों को अनिवार्य किया जा रहा है। इससे स्थानीय स्तर पर संचालित छोटे उद्योगों का भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। बीआईएस के नियमों के लागू होने से पूंजी निवेश बढ़ाना होगा, जगह भी अधिक लगेगी जो वर्तमान स्थिति में छोटे उद्योगों के लिए असंभव है। इसी विषय की गंभीरता को देखते हुए एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मप्र के बैनर पर एक प्रतिनिधिमंडल ने इंदौर सांसद शंकर लालवानी से भेंट की और उन्हें जूते चप्पल निर्माता उद्योगों की परेशानी साझा की। एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश मेहता ने बताया कि फुटवियर से जुड़े सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों पर नए नियमों के खासी परेशानी आने वाली है। इस संबध में सांसद श्री लालवानी के साथ फुटवियर से जुडे उद्योगपतियों की समस्या पर चर्चा की। फुटवियर से जुडे उद्योगपतियों के साथ चर्चा मे उन्होनें कहा कि इस मुद्दे को केन्द्र सरकार के समक्ष रखुंगा साथ ही इस समस्या के समाधान के लिए केन्द्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयुष गोयल के साथ भी कराउंगा। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि यह राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है जिसमें समस्त फुटवियर निर्माताओं पर इसका असर पडेगा।

अध्यक्ष श्री योगेश मेहता ने कहा कि एसोसिएशन भी अपने स्तर पर अन्य राज्यों के फुटवियर निर्माताओं के साथ समन्वय बनाकर एकजुटता के साथ इस मामले को केन्द्र के समक्ष प्रस्तुत करने का पूरजोर प्रयास करेगा जिससे की लघु श्रेणी फुटवियर उद्योग जीवित रह सकेगा। फुटवियर निर्माता गिरिश पंजाबी और अमित संचेती ने बताया कि बीआईएस नियमों के लागू होने पर लघु श्रेणी उद्योग की इनपुट कॉस्ट बहुत अधिक बढ़ जायेगी जिसके कारण इकाईयां अव्यवहार्य हो जाएगी। गरीबों तबको के लिए रोजमर्रा के पहनावे के फुटवियर आज सस्ते मिलते है लेकिन बीआईएस नियमों के लागू होते ही रॉ मटेरियल की लागत बढ़ जायेगी और लागत बढ़ने से कई इकाईयों

का कामकाज असंभव होने से वे बंद हो जायेगी और गरीबों के सस्ते फुटवियर बाजार से गुम हो जायेगें। उद्योगों के बंद होने का सीधा परिणाम रोजगार पर होगा। प्रतिनिधी मंडल में प्रकाश जैन, तरूण व्यास, प्रमोद डफरिया, सहित कई फुटवियर निर्माता उपस्थित थे।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।